भारतीय संघ

बनाम

सोलर पेस्टिसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड वगैरह

4 फ़रवरी 2000

[बी.एन. कृपाल, डी.पी. महापात्रा और आर.पी. सेठी, जे.जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, ध.27(2) परन्तुक (क) से (ग), साथ पढ़ें 28ग और 28घ-अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत-क्या यह आयातित कच्चे माल के संबंध में लागू होता है जिसका उपभोग किसी अंतिम उत्पाद के निर्माण में किया जाता है-माना, अंतिम उत्पाद के निर्माण में उपभोग किए गए आयातित कच्चे माल के संबंध में अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू होगा।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, धारा 27(1)-"ऐसे शुल्क का भार"-इसके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाना इसके दायरे में न केवल प्रत्यक्ष रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कर्तव्य का पारित होना भी होगा।

प्रत्यर्थी ने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए तांबे के स्क्रैप का आयात किया। हालांकि निकासी के

समय माल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान किया गया था, प्रतिवादी ने बाद में एक छूट अधिसूचना के तहत लाभ का दावा करते हुए उक्त शुल्क की वापसी के लिए एक आवेदन दायर किया। सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर ने दावे को खारिज कर दिया।

प्रत्यर्थी द्वारा दायर एक रिट याचिका में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी का रिफंड आवेदन गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। तब राजस्व ने तर्क दिया कि अधिनियम में 1991 में संशोधनों के मद्देनजर, रिफंड के दावे पर धारा 27 (2) के तहत विचार किया जा सकता है, यदि आयातक यह दिखाने में सक्षम था कि उसने आयात शुल्क का बोझ कोई अन्य व्यक्ति नहीं डाला है। उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया और माना कि आयातित कच्चे माल की कैप्टिव खपत के मामले में अन्यायपूर्ण संवर्धन का सवाल ही नहीं उठता। यह संशोधित अधिनियम के तहत तभी उत्पन्न होगा जब उस व्यक्ति द्वारा रिफंड मांगा गया था जिसने आयातित सामान बेचा था और इस प्रक्रिया में, शुल्क का बोझ सीधे खरीदार पर डाल दिया था। राजस्व ने इस न्यायालय में अपील की।

अपील की अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने

अभीनिर्धारित: 1.1 अंतिम उत्पाद के निर्माण में उपभोग किए गए आयातित कच्चे माल के संबंध में अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू होगा।

1.2. जब कच्चे माल के आयात पर लगने वाला पूरा शुल्क या उसका कुछ हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाता है तो अधिनियम की धारा 27(1) के तहत ऐसे शुल्क की वापसी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1.3. शुल्क की वापसी का दावा करने के लिए यह महत्वहीन था कि क्या आयातित माल का उपयोग आयातक द्वारा स्वयं किया गया था और उस पर शुल्क तैयार उत्पाद के खरीदार को दिया गया था या आयातित माल खरीदार को बेचा गया था। दोनों ही स्थिति में अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू होगा।

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1997] 5 एससीसी 536, पर निर्भर

एचएमएम लिमिटेड बनाम प्रशासक, बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन, [1989] सप्लिमेंट 1 एससीआर 353; राजस्थान राज्य बनाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, (1998] 9 एससीसी 708 और भद्राचलम पेपरबोर्ड्स

लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, (1999) 106 ई.एल.टी. 290 एस.सी., संदर्भित

2. अधिनियम की धारा 27(1) शुल्क का भार की बात करती है, न कि शुल्क को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने की। किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में "शुल्क का भार " इसके दायरे में न केवल शुल्क को सीधे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने को ले जाएगी, बल्कि ऐसे मामले भी होंगे जहां इसे अप्रत्यक्ष रूप से पारित किया गया है। जहां कच्चे माल पर भुगतान किया गया शुल्क बेचे जाने वाले तैयार माल की कीमत में जोड़ा जाता है, कच्चे माल पर शुल्क का बोझ तैयार उत्पाद के खरीदार पर डाल दी जाएगी।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 921/1992 आदि

बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.10.91 से डब्ल्यू.पी.सं. 1402/1988

एम.के. बनर्जी, सोली सोराबजी अटॉर्नी जनरल, डी.पी. गुप्ता, सॉलिसिटर जनरल वी.आर. रेड्डी, एम. चन्द्रशेखरन, के.एन. भट्ट, सी.एस.वैद्यनाथन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ए.के. गांगुली, जोसेफ वेल्लापल्ली, जी.एल. सांघी, हरीश एन. साल्वे, एफ.एस. नरीमन, आर.एफ. नरीमन, डी.ए. दवे, के. परासरन, जयंत दास, वी.ए. बोबडे, अशोक एच. देसाई, बी.बी. आहूजा, अनिल बी, दीवान, पी.पी. राव, ए सुब्बा राव, पी. परमेश्वरन, माणिक करंजावाला, वी.बी. मिश्रा, दुष्यन्त दवे, आर. करंजावाला, श्रीमती नंदिनी गोरे, श्रीमती एम. करंजावाला, राजेश कुमार,

अदिति चौधरी, वी. बालचंद्रन, सरवा मित्तर, सुश्री बिराज तिवारी, अशोक के.आर. गुप्ता, मुकुल मुदगा डी.एस.मेहरा, सी.वी.एस. राव, एस.एन. टेरडोल, सुश्री इंद्रा साहनी, मोहिंदर रूपल, आनंद प्रसाद, टी.:.ए राणा, अकील शीराज़ी, डेरियस श्रॉफ, सुश्री अमृता मित्रा, रविंदर नारायण, एस.सी. शर्मा, पोचखानवाला, राजन नारायण, गणेश, पी. मलिक, एन.के. साहू, बी.एन. अग्रवाल, सुश्री निशा बागची, एस. फजल, सागर, पी.एच. पारेख, एम. नानावटी, वी.के. भट्ट, एस.एल. नानावती, वी.के. भट्ट, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वी.के. वर्मा, एनएक्स बाजपेयी, जी.एस. चटर्जी, पी. महाले, बी.वी. देसाई, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, जे.के. दास, के.आर. नागराजा, सोनू भटनागर, वी. श्रीधरन, वी. लक्ष्मीकुमारन, सुश्री अपर्णा झा, एम.के. मोहन, राजीव त्यागी, बी.जे. मेहता, सुश्री अरुणा बनर्जी, सुश्री सुषमा सुर रघुनाथ, पी.आर. तिवारी, जी. प्रकाश, पी. नरसिम्हन, सुश्री सविता शर्मा, दलीप टंडन, के. स्वामी, एम. गौरीशंकर मूर्ति, कृष्ण त्यागी, साजन नारायण, मोहित कपूर, सुश्री रूबी आहूजा, भास्कर राज प्रधान, विक्रम ननकानी, आर.एन. बनर्जी, देवन पारेख, समीर पारेख, ई.आर. कुमार, कृष्ण महाजन, राजू रामचंद्रन, आर.बी. हाथीखानावाला, राजेश कुमार, संदीप मित्तल, निखिल सखारदांडे, सुश्री नीरू वैद, दिलीप टंडन, एस. मुरलीधर, अरविंद पी. दातार, एस.डी. शर्मा, सुश्री अमृता मिश्रा, के.सी. कौशिक, एन.के. बाजपेयी, सुश्री हेमन्तिका व्हाई, फारुख राशिद, सुश्री सुमिता हजारिका, के.के. धवन, सुश्री शोभा, गुपाल जैन, के.सी. कौशिक, बी.के. प्रसाद, पवन कुमार, पी.बी.

अग्रवाल, यू.के. खेतान, डी.एस. मेहरा, एच.एम. सिंह, सी. सिद्धार्थ, प्रज्ञान के. शर्मा, सुश्री अनु साहनी, हेमन्त शर्मा, टी.सी. शर्मा, एआर. माधव राव, ए.के. चोपड़ा, राम एकबाल राय, एम.पी. उपस्थित पक्षों के लिए झा, के. श्रीनिवासन, एस. वलिनायगम और जयदीप गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय **किरपाल, जे.** द्वारा सुनाया गया।

क्या अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत आयातित कच्चे माल के संबंध में लागू होता है जो अंतिम उत्पाद के निर्माण में उपयोग किया जाता है, यह प्रश्न इस पर विचार के लिए उठता है। अपील. उपरोक्त मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, हमें सोलर पेस्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'प्रत्यर्थी ' के रूप में संदर्भित) के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर 1992 की सिविल अपील संख्या 921 के मामले में तथ्यों का संदर्भ लेना होगा। प्रतिवादी ने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए तांबे के स्क्रैप का आयात किया। तांबे के स्क्रैप के आयात के समय प्रत्यर्थी ने अतिरिक्त सीमा शुल्क (जिसे काउंटरवेलिंग शुल्क या सीवीडी के रूप में भी जाना जाता है) के भुगतान से छूट मांगी थी जो सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 35/81 सीई दिनांक 1.3.1981 के तहत उपलब्ध थी। निकासी के समय इस शुल्क का भुगतान किया गया था, बाद में, प्रत्यर्थी ने उपरोक्त छूट के तहत लाभ का दावा करते हुए तांबे के स्क्रैप के आयात के समय भुगतान किए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क की वापसी के लिए एक

आवेदन दायर किया। 1.3.1981 की अधिसूचना. सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर, आदेशानुसार दिनांक 16.2.1985 ने दावे को खारिज कर दिया और माना कि आयातित तांबे के स्क्रैप का सही मूल्यांकन किया गया था

उक्त दावे की अस्वीकृति के तीन साल बाद, प्रत्यर्थी द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। उसमें यह दावा किया गया था कि उपरोक्त छूट अधिसूचना रसायनों के निर्माण में उपयोग के लिए तांबे के उत्पाद शुल्क के भुगतान से पूरी छूट देती है। इसलिए, जब तांबे के स्क्रैप को रसायनों के निर्माण में उपयोग के लिए आयात किया जाता था, तो आयातित तांबे के स्क्रैप पर अतिरिक्त सीमा शुल्क (काउंटरवेलिंग शुल्क) नहीं लगाया जा सकता था।

उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी का रिफंड आवेदन गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने तब सीमा शुल्क अधिकारियों की ओर से उठाए गए विवाद पर विचार किया कि रिफंड के दावे पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (इसके बाद में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) में 1991 में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होगा। कार्य')। यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (2) की शुरूआत के साथ, रिफंड के दावे पर विचार किया जा सकता है यदि आयातक यह साबित करने में सक्षम था कि उसने इस तरह के

शुल्क का बोझ किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला है। . दूसरे शब्दों में, दलील यह थी कि कर्तव्य की अतिरेक, जिसका भार पहले ही दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया है, के परिणामस्वरूप अन्यायपूर्ण संवर्धन होगा और अधिनियम में किए गए संशोधनों के मद्देनजर, इस तरह के अन्यायपूर्ण संवर्धन की अनुमति नहीं है।

अधिनियम में जो संशोधन किए गए, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करने की मांग की गई कि माल का निर्माता या आयातक शुल्क की वापसी का हकदार नहीं होगा यदि उसने पहले ही ऐसे शुल्क का बोझ खरीदार को हस्तांतरित कर दिया है। इस बात का प्रमाण देने का भार कि शुल्क का भार खरीदार को नहीं दिया गया है, रिफंड का दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा। उच्च न्यायालय, अधिनियम की धारा 27, 28सी और 280 की व्याख्या करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आयातित कच्चे माल की कैप्टिव खपत के मामले में अन्यायपूर्ण संवर्धन का सवाल ही नहीं उठता। इसके अनुसार, संशोधित अधिनियम के तहत अन्यायपूर्ण संवर्धन का सवाल तब उठेगा जब उस व्यक्ति द्वारा रिफंड मांगा जाएगा जिसने आयातित सामान बेचा है और इस प्रक्रिया में, शुल्क का बोझ सीधे खरीदार पर डाल दिया है। उच्च न्यायालय के अनुसार, यह संशोधित अधिनियम की धारा 28डी में निहित उपधारणा के साथ पढ़ी गई धारा 27(2) के परंतुक के खंड (ए), (बी) और (सी) से स्पष्ट था।

इस अपील में, इस सवाल के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि क्या प्रतिवादी काउंटरवेलिंग शुल्क के भुगतान के संबंध में छूट अधिसूचना का लाभ पाने का हकदार था। इसलिए, हम इस धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय का निर्णय कि प्रत्यर्थी उक्त लाभ का हकदार था, सही था और वह आम तौर पर उस शुल्क की वापसी का हकदार होगा जो उसने भुगतान किया था।

अपीलकर्ता की ओर से, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि मा/अटलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1997) 5 एससीसी 536 मामले में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम की संशोधित धारा 27 की वैधता को बरकरार रखा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (2) के अवलोकन से पता चलता है कि आयातक पर यह साबित करने की जिम्मेदारी थी कि उसने शुल्क की राशि की वापसी का दावा करने से पहले किसी अन्य व्यक्ति पर शुल्क का बोझ नहीं डाला है।

हालाँकि, इस अपील में प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। उक्त प्रावधान को अधिनियम की धारा 28 सी और डी के साथ पढ़ा जाना चाहिए और आयातित कच्चे माल की कैप्टिव खपत के मामले में अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है।

प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने से पहले 1991 में संशोधन के बाद अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को देखना आवश्यक है। धारा 27, 28 सी और 28 डी इस प्रकार हैं:

धारा 27. शुल्क की वापसी का दावा- (1) कोई भी व्यक्ति किसी शुल्क की वापसी का दावा कर रहा है

(i) मूल्यांकन के आदेश के अनुसरण में उसके द्वारा भुगतान किया गया; या

(ii) उसके द्वारा वहन किया गया, ऐसे शुल्क और ब्याज की वापसी के लिए आवेदन कर सकता है, यदि ऐसे शुल्क पर कोई भुगतान किया गया हो तो वह सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त को आवेदन कर सकता है

(ए) एक वर्ष की समाप्ति से पहले किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या सरकार द्वारा या किसी शैक्षिक, अनुसंधान या धर्मार्थ संस्थान या अस्पताल द्वारा किए गए किसी भी आयात के मामले में;

(बी) किसी भी अन्य मामले में, छह महीने की समाप्ति से पहले, (ऐसी ड्यूटी पर भुगतान किए गए शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो) के भुगतान की तारीख से (ऐसे रूप और तरीके से) जैसा कि बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है इस ओर से और आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (धारा 28 सी में निर्दिष्ट दस्तावेजों सहित)

संलग्न किए जाएंगे, जो आवेदक यह स्थापित करने के लिए प्रस्तुत कर सके कि संबंध में (ऐसी ड्यूटी पर भुगतान की गई शुल्क और ब्याज की राशि, यदि कोई हो) जिसके लिए इस तरह के रिफंड का दावा किया गया है, उससे एकत्र किया गया था, या उसके द्वारा भुगतान किया गया था इस तरह की घटना (शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, ऐसे शुल्क पर भुगतान किया गया) उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई थी:

बशर्ते कि कहां केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारंभ होने से पहले रिफंड के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे आवेदन को इस उप-धारा के तहत किया गया माना जाएगा और उसी के अनुसार निपटाया जाएगा। उपधारा (2) के प्रावधान:

बशर्ते कि एक वर्ष या छह महीने की सीमा, जैसा भी मामला हो, लागू नहीं होगी, जहां ऐसी ड्यूटी पर भुगतान किया गया कोई शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, विरोध के तहत भुगतान किया गया है:

(बशर्ते यह भी कि उन वस्तुओं के मामले में जिन्हें धारा 25 की उप-धारा (2) के तहत जारी एक विशेष आदेश द्वारा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, एक वर्ष या छह महीने की सीमा, जैसा भी मामला हो, की गणना की जाएगी ऐसे आदेश जारी होने की तारीख से)

(स्पष्टीकरण 1 - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, आयातक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में, ऐसे शुल्क पर भुगतान किए गए शुल्क और ब्याज के भुगतान की तारीख, यदि कोई हो, को "खरीद की तारीख" के रूप में माना जाएगा। माल का" ऐसे व्यक्ति द्वारा)।

(स्पष्टीकरण 2.-जहां किसी भी शुल्क का भुगतान धारा 18 के तहत अनंतिम रूप से किया जाता है, एक वर्ष या छह महीने की सीमा, जैसा भी मामला हो, अंतिम मूल्यांकन के बाद शुल्क के समायोजन की तारीख से गणना की जाएगी।)

(2) यदि, ऐसे किसी आवेदन की प्राप्ति पर, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त संतुष्ट हैं कि आवेदक द्वारा भुगतान किए गए ऐसे शुल्क पर भुगतान किया गया शुल्क और ब्याज का पूरा या कुछ हिस्सा, यदि कोई हो, वापसी योग्य है, तो वह तदनुसार आदेश दे सकता है और इस प्रकार निर्धारित राशि निधि में जमा की जाएगी:

बशर्ते कि इस उप-धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के तहत सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित ऐसे शुल्क पर भुगतान की गई शुल्क और ब्याज की राशि, यदि कोई हो, निधि में जमा किए जाने के बजाय, आवेदक को भुगतान की जाएगी, यदि ऐसी राशि प्रासंगिक है

(ए) आयातक द्वारा भुगतान किए गए ऐसे शुल्क पर भुगतान किए गए शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, यदि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे शुल्क पर भुगतान किए गए शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, पर पारित नहीं किया है; (बी) किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए किए गए आयात पर ऐसे शुल्क पर भुगतान किया गया शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो; (सी) खरीदार द्वारा वहन किए गए ऐसे शुल्क पर भुगतान किया गया शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, यदि उसने ऐसे शुल्क और ब्याज की घटना को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया है; (डी) धारा 26 में निर्दिष्ट निर्यात शुल्क; (ई) धारा 74 और 75 के तहत देय शुल्क की वापसी

(एफ) आवेदकों के किसी अन्य वर्ग द्वारा वहन किए गए शुल्क पर भुगतान किया गया शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है: बशर्ते कि पहले परंतुक के खंड (एफ) के तहत कोई अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि केंद्र सरकार की राय में ऐसी ड्यूटी पर भुगतान किए गए शुल्क और ब्याज की घटना, यदि कोई हो, संबंधित व्यक्तियों द्वारा किसी को नहीं दी गई हो।

28सी. माल की कीमत उस पर भुगतान किए गए शुल्क की राशि को इंगित करने के लिए - इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य

कानून में किसी भी बात के बावजूद, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी माल पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, माल की निकासी के समय , मूल्यांकन, बिक्री चालान और अन्य समान दस्तावेजों से संबंधित सभी दस्तावेजों में प्रमुखता से इंगित करें, ऐसे शुल्क की राशि जो उस कीमत का हिस्सा बनेगी जिस पर ऐसा सामान बेचा जाना है।

28डी. यह उपधारणा कि शुल्क का पूरा भार क्रेता पर डाल दिया गया है - प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के तहत किसी भी सामान पर शुल्क का भुगतान किया है, जब तक कि उसके द्वारा इसके विपरीत साबित नहीं किया जाता है, यह माना जाएगा कि उसने ऐसे शुल्क का पूरा भार क्रेता को दे दिया है।"

मफतलाल के मामले (उपर्युक्त) में अधिनियम की धारा 27 की वैधता और उसी की व्याख्या इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई। पृष्ठ 631 पर वैधता को बरकरार रखते हुए, यह देखा गया कि "कैप्टिव खपत के मामले में स्थिति को इस राय में हमारे द्वारा नहीं निपटाया गया है। हम उस प्रश्न को खुला छोड़ देते हैं।" यह वह प्रश्न है जो अब सामने आया है वर्तमान अपीलों पर विचार। धारा 27(1) का पहला प्रावधान उन मामलों से संबंधित है जहां रिफंड के लिए आवेदन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 के शुरू होने से पहले किया गया था। इस प्रावधान के अनुसार, ऐसे आवेदन के लिए रिफंड को उप-धारा (2)

के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा। वर्तमान मामलों में, हम कच्चे माल के आयात से चिंतित हैं जहां शुल्क का भुगतान किया गया था और रिफंड के लिए आवेदन पहले किए गए थे। संशोधन अधिनियम, 1991 का प्रारंभ। ऐसे सभी आवेदनों को अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाना आवश्यक है।

अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (1) कुछ मामलों में शुल्क और ब्याज की वापसी के लिए दावा करने और उस सीमा की अवधि का प्रावधान करती है जिसके भीतर ऐसा दावा किया जाना है। यह उप-धारा, अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि आवेदक को यह स्थापित करना होगा कि शुल्क और ब्याज की राशि जिसके संबंध में रिफंड का दावा किया गया है, उससे एकत्र की गई थी, या उसके द्वारा भुगतान किया गया था और शुल्क और ब्याज की घटना, यदि कोई भी, उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया गया था। धारा 27 की उप-धारा (2), जो वर्तमान मामले में लागू होती है, प्रावधान करती है कि यदि सहायक आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि शुल्क या ब्याज का पूरा या कुछ हिस्सा वापसी योग्य है, तो उस प्रभाव के अनुसार एक आदेश दिया जाएगा और इस प्रकार निर्धारित राशि निधि में जमा की जाएगी। अधिनियम की धारा 2(21ए) के अनुसार, "फंड" शब्द का अर्थ केंद्रीय उत्पाद शुल्क और

नमक अधिनियम, 1944 की धारा 12सी के तहत स्थापित उपभोक्ता कल्याण कोष है।

अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (2) के परंतुक का खंड (ए) हालांकि यह निर्धारित करता है कि देय रिफंड की राशि को निधि में जमा नहीं किया जाएगा और अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक को भुगतान किया जाएगा, यदि ऐसा है रिफंड की राशि उस शुल्क और ब्याज से संबंधित है जो आयातक द्वारा भुगतान किया गया है और यदि उसने इसका भार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया है। दूसरे शब्दों में यदि यह नहीं दिखाया जा सकता है कि शुल्क, जिसके संबंध में रिफंड का दावा किया गया है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया है तो ऐसी स्थिति में देय रिफंड की राशि फंड में जमा कर दी जाएगी।

अधिनियम की धारा 28 सी और डी को नए अध्याय वीए में शामिल किया गया है जिसका शीर्षक है "रिफंड के उद्देश्य के लिए माल की कीमत आदि में शुल्क की मात्रा का संकेत"। धारा 28सी किसी भी सामान पर शुल्क का भुगतान करने वाले अन्य व्यक्ति के लिए माल की निकासी के समय, मूल्यांकन, बिक्री चालान और अन्य समान दस्तावेजों से संबंधित दस्तावेजों में ऐसे शुल्क की राशि का संकेत देना अनिवार्य बनाती है जो इसका हिस्सा बनेगी। उस कीमत पर जिस पर ऐसा सामान बेचा जाना है। धारा 28डी में एक धारणा है कि शुल्क की घटना खरीदार को दे दी गई है,

लेकिन यह धारणा खंडन योग्य है। इस बात के प्रमाण के अभाव में कि ऐसी ड्यूटी खरीदार को हस्तांतरित नहीं की गई है, धारा 28डी में प्रावधान है कि विक्रेता द्वारा खरीदार को ऐसी ड्यूटी हस्तांतरित करना माना जाएगा

प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि संशोधित प्रावधान की योजना पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए और अधिनियम की धारा 27 को अधिनियम की धारा 28डी के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि केवल एक प्रकार के रिफंड के संदर्भ में अनुमान प्रदान करने का इरादा नहीं हो सकता है और दूसरे में नहीं, क्योंकि पुन: बिक्री के मुकाबले कैप्टिव उपभोग के मामले में अनुमान की आवश्यकता अधिक होगी। जैसे आयातित वस्तुओं का. इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि अनुमान की अनुपस्थिति से यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्यायपूर्ण संवर्धन के प्रावधानों का उद्देश्य कैप्टिव उपभोग के मामलों पर लागू होना नहीं था।

हम विद्वान वकील के उपरोक्त कथन से सहमत होने में असमर्थ हैं। अधिनियम की धारा 27, एक तरह से, अपने आप में संपूर्ण संहिता है, जो शुल्क वापसी के दावे से संबंधित है। धारा 27(1) द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया उक्त धारा में संशोधन के बाद रिफंड के लिए आवेदन दायर करने के मामले में लागू होती है। उप-धारा (1) में रिफंड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को यह स्थापित करने के लिए दस्तावेज और साक्ष्य (धारा

28 सी में संदर्भित दस्तावेजों सहित) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है कि शुल्क की राशि, जिसके संबंध में रिफंड का दावा किया गया है, एकत्र या भुगतान किया गया था। उसके द्वारा और ऐसे कर्तव्य की घटना उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपी गई थी।

"ऐसे शुल्क का भार..." शब्दों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 27(1) शुल्क का भार की बात करती है, न कि शुल्क को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने की। किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में "शुल्क का भार " इसके दायरे में न केवल शुल्क को सीधे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने को ले जाएगी, बल्कि ऐसे मामले भी होंगे जहां इसे अप्रत्यक्ष रूप से पारित किया गया है। जहां कच्चे माल पर भुगतान किया गया शुल्क बेचे जाने वाले तैयार माल की कीमत में जोड़ा जाता है, कच्चे माल पर शुल्क का बोझ तैयार उत्पाद के खरीदार पर डाल दी जाएगी। उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलेगा कि जब कच्चे माल के आयात पर लगने वाला पूरा शुल्क या उसका कुछ हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है तो अधिनियम की धारा 27(1) के तहत रिफंड के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिनियम की धारा 27(2) उन मामलों से संबंधित है जहां रिफंड के लिए आवेदन 1991 में अधिनियम में संशोधन से पहले किया गया था। परंतुक की उप-धारा (ए) इसमें निहित

प्रावधानों के समान है। अधिनियम की धारा 27(1) यानी आयातक द्वारा भुगतान किए गए शुल्क की वापसी की अनुमति दी जाएगी यदि उसने ऐसे शुल्क की घटना को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया हो। अधिनियम की धारा 28 सी उन वस्तुओं के संदर्भ में होगी जिन्हें मंजूरी दे दी गई है और निस्संदेह कैप्टिव कंजम्प्टियून के मामलों में इसका कोई आवेदन नहीं होगा। इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि चूंकि अधिनियम की धारा 28 सी कैप्टिव उपभोग के लिए आयातित वस्तुओं के मामलों में लागू नहीं की जा सकती है, इसलिए, ऐसे मामलों में अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, अधिनियम की धारा 27 को 1991 में किए गए संशोधनों के साथ फिर से तैयार किया गया है और उक्त धारा को आवश्यक रूप से अधिनियम की धारा 27 सी और डी के साथ पढ़ा जाना जरूरी नहीं है। यदि आयातित कच्चे माल पर भुगतान किए गए शुल्क की घटना को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया है, तो उस मामले में अधिनियम की धारा 27(2) के प्रावधानों के आधार पर, जहां रिफंड के लिए आवेदन 1991 से पहले किया गया था, रिफंड देय शुल्क का भुगतान आवेदक को किया जाएगा।

भले ही मफतला के मामले में (उपरोक्त) बंदी उपभोग के संबंध में प्रश्न खुला था, इस न्यायालय को अधिनियम की धारा 27 की व्याख्या करने के लिए बुलाया गया था। उठाए गए विभिन्न तर्कों पर चर्चा करने

और निर्णय लेने के बाद, जीवन रेड्डी, जे के बहुमत के फैसले ने सुविधा के लिए पृष्ठ 631 पर पैरा 108 के तहत उन प्रस्तावों को निर्धारित किया जो फैसले से निकले थे। रिफंड के दावे के संबंध में, पृष्ठ 633 पर यह इस प्रकार देखा गया:

> "(iii) रिफंड का दावा, चाहे उपरोक्त प्रस्ताव (i) में विचारित अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया हो या उपरोक्त प्रस्ताव (ii) द्वारा विचारित स्थितियों में एक मुकदमे या रिट याचिका में किया गया हो, केवल तभी सफल हो सकता है जब याचिकाकर्ता /वादी आरोप लगाता है और स्थापित करता है कि उसने कर्तव्य का बोझ किसी अन्य व्यक्ति/अन्य व्यक्तियों पर नहीं डाला है। उसके रिफंड दावे को केवल तभी अनुमति/निर्णय दिया जाएगा जब वह यह स्थापित कर ले कि उसने कर्तव्य का बोझ उस पर नहीं डाला है या जिस हद तक नहीं डाला है, जैसा भी मामला हो। चाहे क्षतिपूर्ति के दावे को संवैधानिक अनिवार्यता के रूप में माना जाए या वैधानिक आवश्यकता के रूप में, यह न तो पूर्ण अधिकार है और न ही बिना शर्त दायित्व है, बल्कि उपरोक्त आवश्यकता के अधीन है, जैसा कि निर्णय के मुख्य

भाग में बताया गया है। जहां कर्तव्य का बोझ डाल दिया गया है, वहां दावेदार यह नहीं कह सकता कि उसे कोई वास्तविक हानि या पूर्वाग्रह हुआ है। ऐसे मामले में वास्तविक हानि या पूर्वाग्रह उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है जिसने अंततः बोझ उठाया है

और केवल वही व्यक्ति वैध रूप से इसकी वापसी का दावा कर सकता है। लेकिन जहां ऐसा व्यक्ति आगे नहीं आता है या किसी या अन्य कारण से उसे राशि लौटाना संभव नहीं है, तो यह उचित और उचित है कि वह राशि राज्य द्वारा यानी लोगों द्वारा अपने पास रख ली जाए। ऐसे प्रस्ताव में कोई अनैतिकता या अनौचित्य शामिल नहीं है।

अन्यायपूर्ण उत्पीडन का सिद्धांत एक न्यायसंगत और हितकारी सिद्धांत है। कोई भी व्यक्ति दोनों छोर से शुल्क वसूलने की कोशिश नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, वह

एक तरफ से अपने क्रेता से शुल्क नहीं ले सकता है और राज्य से भी वही शुल्क इस आधार पर नहीं ले सकता है कि यह उससे कानून के विपरीत वसूल किया गया है। न्यायालय की शक्ति का प्रयोग किसी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से अपमानित करने के लिए नहीं किया जाता है। हालाँकि, अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत राज्य पर लागू नहीं होता है। राज्य देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी लोगों के अन्यायपूर्ण अपमान के बारे में बात नहीं कर सकता।"

हमारी राय है कि उपरोक्त टिप्पणियाँ कैप्टिव खपत के मामले में भी लागू होंगी। शुल्क की वापसी का दावा करने के लिए यह महत्वहीन है कि क्या आयातित माल का उपयोग आयातक द्वारा स्वयं किया जाता है और उस पर शुल्क तैयार उत्पाद के खरीदार को दिया जाता है या आयातित माल को कर की घटना के साथ बेचा जाता है। क्रेता. किसी भी मामले में अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू होगा और आयात शुल्क का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अधिनियम की धारा 27 की स्पष्ट भाषा के कारण रिफंड पाने का हकदार नहीं होगा। किसी अन्य व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष रूप से कर का बोझ डालने के बाद, यह स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण संवर्धन का मामला होगा यदि आयातक/विक्रेता पहले से ही कर की घटना के बावजूद सरकार से भुगतान किए गए शुल्क का रिफंड प्राप्त करने में सक्षम है।

प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया था कि आयातित वस्तुओं की कैप्टिव खपत के मामलों में, निर्धारिती के लिए यह स्थापित करना असंभव होगा कि क्या शुल्क घटक तैयार उत्पादों के खरीदारों को दिया गया है या आयातक द्वारा स्वयं वहन किया गया है। . यह साबित करने में कठिनाई कि आयातक द्वारा वहन किए गए शुल्क का भार तैयार उत्पाद के खरीदार को नहीं दिया गया है, धारा 27 को अलग से व्याख्या करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। यह संभव नहीं है कि किसी भी मामले में कोई आयातक यह साबित नहीं कर पाएगा कि आयातित कच्चे माल पर लगाए गए शुल्क का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया है। वास्तव में सूर्या रोशिनी लिमिटेड के खिलाफ सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दायर 1999 की सिविल अपील संख्या 4381 में, आयातक ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अंतिम उत्पाद की लागत का विवरण देने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था और आयुक्त (अपील) ने इसे एक तथ्य के रूप में पाया था। आयातित कच्चे माल पर चुकाए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क का घटक तैयार उत्पाद की लागत में शामिल नहीं था। इस निष्कर्ष की सत्यता पर

जाए बिना हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि कैप्टिव खपत के मामलों में भी, आयातक के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष यह दिखाना और साबित करना संभव होना चाहिए कि कच्चे माल पर शुल्क की घटना, जिसके संबंध में रिफंड दावा किया गया है, आयातक द्वारा किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया गया है।

अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत की प्रयोज्यता के सवाल पर विचार करते समय उच्च न्यायालय ने एचएमएम लिमिटेड और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया था। प्रशासक, बैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन, बैंगलोर और अन्य, (1989] अनुपूरक । एससीआर 353। यह मामला शहर की सीमा में प्रवेश पर माल पर चुंगी लगाने से संबंधित था। भले ही उक्त वस्तुओं पर चुंगी वसूल की गई थी। नगरपालिका सीमा के भीतर कोई उपयोग या खपत नहीं थी। इस न्यायालय ने माना कि भुगतान की गई चुंगी की राशि वापसी योग्य थी। इस संदर्भ में, निगम की ओर से एक तर्क उठाया गया था कि रिफंड नहीं दिया जा सकता क्योंकि अनुचित होने की संभावना थी। दावेदार का संवर्धन। इस न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चुंगी कच्चे माल के प्रवेश पर एक शुल्क था जो निर्माता या निर्माता द्वारा देय था। यह तैयार उत्पादों को बाहर ले जाने पर लगने वाला शुल्क नहीं था। जिसके संबंध में शुल्क वसूला गया होगा या उपभोक्ताओं को दी गई लागत में जोड़ा गया

होगा। इस न्यायालय ने तब निष्कर्ष निकाला कि "ऐसी स्थिति में, इस मामले में 'अनुचित संवर्धन' का कोई सवाल संभवतः नहीं उठ सकता है। यह निर्णय इस प्रकार है स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में लागू नहीं होता जहां अन्यायपूर्ण संवर्धन का प्रश्न उठता है।

राजस्थान राज्य और अन्य बनाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, [1998] 9 एससीसी 708 में, इस न्यायालय ने हलफनामे में दिए गए कथन को स्वीकार कर लिया। निर्धारिती की ओर से इस आशय का कि परिशोधित स्पिरिट पर भुगतान किया गया अतिरिक्त शुल्क, जिसके संबंध में रिफंड का दावा किया गया था, अंतिम उत्पाद के किसी भी उपभोक्ता को नहीं दिया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने माना कि अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू नहीं होता। अंत में, हमारा ध्यान भद्राचलम पेपरबोर्ड्स लिमिटेड बनाम सरकार के मामले की ओर आकर्षित हुआ। आंध्र प्रदेश की, (1999) (106) ई.एल.टी. 290 (एस.सी.)। इस मामले में गलती से भुगतान किए गए बिक्री कर की वापसी के लिए दावा किया गया था। उच्च न्यायालय ने रिफंड से इनकार कर दिया था क्योंकि उसका मानना था कि निर्धारिती ने उपभोक्ता पर बोझ डाल दिया होगा, जिससे अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू हुआ होगा। करदाता की अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय यह मानने में सही नहीं था कि कर का बोझ ग्राहक पर डाला गया था। इस न्यायालय ने तथ्यों पर

आगे कहा कि अपीलकर्ता द्वारा उपभोक्ता को कर दायित्व देने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए, यह मामला प्रत्यर्थी के लिए कोई सहायता नहीं हो सकता है।

उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की सही व्याख्या नहीं की है और, हमारी राय में, अधिनियम की धारा 27 में शामिल अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत आयातित कच्चे माल के संबंध में लागू होगा जो अंतिम उत्पाद के निर्माण में इनका उपभोग किया जाता है। सौर कीटनाशकों के मामले (सुप्रा) में उच्च न्यायालय द्वारा यह तय नहीं किया गया था कि शुल्क का भार उपभोक्ता को दिया गया था या नहीं, क्योंकि उसकी राय में कैप्टिव उपभोग के मामलों में अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता था। सोलर पेस्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड के मामले में। लिमिटेड, इसलिए, हम इस प्रश्न पर नहीं जाते हैं कि क्या शुल्क का भार प्रत्यर्थी द्वारा हस्तांतरित नहीं की गई थी। तदनुसार, इस अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया जाता है, जिसका प्रभाव यह होगा कि सोलर पेस्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। इस न्यायालय में सोलर पेस्टिसाइड्स प्राइवेट द्वारा दायर रिट याचिका (सी) संख्या 189/1993 को भी खारिज कर दिया गया है। कोई खर्च नहीं

सिविल अपील संख्या 4381/1999

उपर्युक्त मामले में प्रतिवादी ने कॉइल्स में प्राइम क्वालिटी हॉट रोल्ड स्टील का आयात किया था, जिस पर शुल्क का भुगतान किया गया था। माल के वर्गीकरण के आधार पर शुल्क की वापसी का दावा किया गया था। अंततः प्रतिवादी सफल हुआ और कलेक्टर (अपील), बॉम्बे ने भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया। रिफंड के लिए 13 आवेदन दायर किए गए और सहायक कलेक्टर ने उन्हें निम्नानुसार समूहीकृत किया:

(i) सूची में क्रम संख्या 1-6 पर प्रविष्टियों के बिल पर आधारित दावे जो विभाग को 22.6.1989 को प्राप्त हुए थे

(ii) क्रम संख्या 7-9 और पर प्रविष्टियों की पहाड़ियों से संबंधित दावे

(iii) शेष 4 बिलों से उत्पन्न दावे।

पहली श्रेणी के संबंध में सहायक कलेक्टर ने माना कि दावे सीमा से वर्जित थे। दूसरी श्रेणी के तहत आने वाले दावों को उनके द्वारा अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत के मद्देनजर चलने योग्य नहीं माना गया और तीसरी श्रेणी के तहत किए गए दावों को समय से पहले माना गया। सहायक कलेक्टर के समक्ष, प्रतिवादी ने यह दिखाने के प्रयास में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था कि शुल्क, जिसके संबंध में

रिफंड का दावा किया जा रहा था, तैयार उत्पादों के उनके ग्राहकों को नहीं दिया गया था। हालाँकि, सहायक कलेक्टर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उक्त प्रमाणपत्र यह स्थापित नहीं करता है कि शुल्क ग्राहकों को नहीं दिया गया था। कलेक्टर (अपील) ने सहायक कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया और शुल्क राशि रुपये वापस करने का निर्देश दिया। 85, 71,688.34. इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि कलेक्टएनआर (अपील) ने प्रतिवादी द्वारा उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रस्तुत प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया, जिसने प्रमाणित किया था कि प्रतिवादी ने अतिरिक्त शुल्क राशि को शामिल नहीं किया है, जिसके संबंध में रिफंड का दावा किया जा रहा था, उनके तैयार की लागत में उत्पाद. कलेक्टर (अपील) ने उक्त प्रमाणपत्र को स्वीकार करते हुए धन वापसी की अनुमति दी।

राजस्व ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की। सोलर पेस्टिसाइड्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1992) (57) 201 में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा अपील खारिज कर दी गई थी, एक निर्णय, जिसे हमने अब माना है कि वह सही नहीं था। ट्रिब्यूनल ने इस सवाल पर ध्यान नहीं दिया कि क्या वास्तव में रिफंड का भुगतान करने का आदेश दिए जाने की स्थिति में अन्यायपूर्ण संवर्धन होगा। इस प्रश्न पर न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय की आवश्यकता है। ऊपर बताए गए कारणों से, सोलर पेस्टिसाइड्स (इंडिया) लिमिटेड में ट्रिब्यूनल का निर्णय

कि अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत कैप्टिव खपत के मामलों पर लागू नहीं होता है, स्पष्ट रूप से गलत है। इसलिए, हम उसकी अपील की अनुमति देते हैं, ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द करते हैं और उसे इस सवाल पर नए सिरे से राजस्व की अपील पर फैसला करने का निर्देश देते हैं कि क्या तथ्यों के आधार पर अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू होगा या नहीं।

सिविल अपील संख्या 2711/1999

सिविल अपील संख्या 921/1999 में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द करते हैं और उसे इस सवाल पर नए सिरे से राजस्व की अपील पर निर्णय लेने का निर्देश देते हैं कि क्या अन्याय का सिद्धांत तथ्यों के आधार पर संवर्धन लागू होगा या नहीं।

सिविल अपील संख्या 6113/1999

शुल्क की वापसी के दावे में, प्रतिवादी ने दो तर्क उठाए। सबसे पहले यह कि शुल्क का भार उपभोक्ता पर नहीं डाला गया था और अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू नहीं हुआ था। दूसरा तर्क यह था कि किसी भी स्थिति में, सोलर पेस्टिसाइड्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1992) (57) ईएलटी 201 के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत था कैप्टिव उपभोग के मामलों में

लागू नहीं है। न तो सहायक आयुक्त और न ही आयुक्त (अपील) ने दोनों में से किसी भी तर्क को स्वीकार किया। यह माना गया कि प्रतिवादी साबित करने में विफल रहा; आयातित वस्तुओं के संबंध में शुल्क की घटना को आगे नहीं बढ़ाया गया था। निर्धारिती द्वारा दायर अपील पर, ट्रिब्यूनल ने सौर कीटनाशकों में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इसकी अनुमति दी (इंडिया) लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (1992) (57) ईएलटी 201, जिसे हमने अब माना है, एक अच्छा कानून नहीं है। ट्रिब्यूनल ने यह तय नहीं किया कि निर्धारिती ने उपभोक्ता को शुल्क की घटना से अवगत कराया था या नहीं। उस विवाद पर विचार करने की आवश्यकता होगी। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांक 6.7.1999 के फैसले को रद्द करते हैं और उसे इस सवाल पर नए सिरे से निर्धारिती द्वारा अपील पर निर्णय लेने का निर्देश देते हैं कि क्या की घटना आयातित कच्चे माल पर शुल्क आयातक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया था।

सिविल अपील संख्या 5688-89/1995 सिविल अपील संख्या 921/1992 में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह अपील स्वीकार की जाती है।

1996 की सिविल अपील संख्या 16890, 16894 और 16885

सिविल अपील संख्या 921/1992 में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, इन अपीलों को अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय के निर्णयों को रद्द कर दिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि प्रतिवादी द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

सिविल अपील संख्या 1565/1999 ट्रिब्यूनल ने सोलर पेस्टिसाइड्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1992) (57) ईएलटी 201 में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद कलेक्टर (अपील) के आदेश को बरकरार रखा। सिविल में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए 1992 की अपील संख्या 921, यह अपील स्वीकार की जाती है, ट्रिब्यूनल का निर्णय रद्द किया जाता है। चूंकि ट्रिब्यूनल ने इस सवाल पर ध्यान नहीं दिया कि अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था या नहीं, ट्रिब्यूनल को अपील पर नए सिरे से फैसला करना चाहिए।

1999 की सिविल अपील संख्या 5407-5409 और 6261 ट्रिब्यूनल ने सौर कीटनाशकों के मामले (उपरोक्त) में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस आधार पर रिफंड के भुगतान की अनुमति दी थी कि कैप्टिव खपत के मामले में अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। 1992 की सिविल अपील संख्या 921 में हमारे फैसले को ध्यान में रखते हुए, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया है, राजस्व की इन अपीलों की अनुमति है। कोई खर्च नहीं।

अपीलें स्वीकार की गईं और याचिका खारिज कर दी गई

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ***श्री जयपाल जाणी*** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)